RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 MAY 2022 TO 17 MAY 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 35 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

दूध की पन्नियों, प्लास्टिक की बोतलों से बनाया जा सकेगा प्लाइवुड Page 2

क्रिप्टो निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका, 28 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी में जीएसटी परिषद Page 3

टाटा मोटर्स ने नए एस ईवी के साथ ई-कार्गो के क्षेत्र में परिवहन समाधान पेश Page 7

editoria!

बढ़ता सेवा निर्यात

वित्त वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में निर्यात 254.4 अरब डॉलर रहा, जो अभूतपूर्व है. इसी के साथ भारत का कुल निर्यात 676.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2020 में 538 अरब डॉलर और 2021 में लगभग 498 अरब डॉलर रहा था. सेवा क्षेत्र में यह उपलब्धि दूरसंचार, कंप्यूटर व सूचना सेवाओं और अन्य कारोबारी सेवाओं के बढ़ते निर्यात से हासिल हुई है. वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 206 अरब डॉलर रहा था. कुछ दिन पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी थी कि बीते वर्ष के लिए सेवा क्षेत्र में निर्यात का प्रारंभिक लक्ष्य 225 अरब डॉलर रखा गया था, जिसे संशोधित कर 250 अरब डॉलर किया गया था. इस लक्ष्य को भी पार कर लिया गया है. इससे इंगित होता है कि हालिया वर्षों में भारत बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिस (बीपीओ) तक सीमित रहने के बजाय आधुनिक तकनीक से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है. इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अप्रैल से दिसंबर, 2021 की अवधि में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात का मूल्य लगभग 92 अरब डॉलर रहा था, जबकि इस अंतराल में इन सेवाओं में 10.48 अरब डॉलर का ही आयात करना पड़ा था. इससे यह भी संकेत मिलता है कि सूचना तकनीक में सेवा क्षेत्र घरेलू बाजार के लिए भी बड़ी मात्रा में आपूर्ति मुहैया करा रहा है. दिसंबर तक पेशेवर और कारोबारी सेवाओं का निर्यात 42.13 अरब रहा था, पर 37.81 अरब डॉलर मूल्य की ऐसी सेवाओं का आयात भी करना पड़ा था. इस आयात का एक बड़ा कारण देश में बढ़ता निवेश है, पर इसमें बेहतरी की संभावनाएं हैं. यह भी महत्वपूर्ण है कि 2021-22 में लगभग हर क्षेत्र में निर्यात बढ़ा है. बीते साल हर घंटे 48 मिलियन डॉलर का मूल्य का निर्यात हुआ है. कोरोना महामारी के दौर में भारत वैश्विक मांग की पूर्ति में बड़े हिस्सेदार के रूप में उभर रहा है. गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर ने इसमें अहम भूमिका निभायी है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ जिला स्तर और किसानों एवं उद्यमियों तक सीधे पहुंचकर निर्यात को प्रोत्साहित किया है. वर्ष 2021-22 में 50 अरब मूल्य के कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है. वर्ष 2016-17 से कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार सक्रिय है. पिछले साल निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी है. कोरोना काल में सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि उद्यमियों और कारोबारियों को वित्त संबंधी परेशानियां कम से कम हों.इसके अलावा नियमों एवं प्रक्रियाओं में भी अनेक सकारात्मक सुधार किये गये. इसका लाभ हमें दिखने लगा है. चूंकि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं तथा वैश्विक आपूर्ति में अनेक बाधाएं हैं, इस कारण हमारे आयात का खर्च भी बढ़ा है, जिसके समय के साथ संतुलित होने की आशा है.

सस्ता होगा खाने का तेल?

निर्मला सीतारमण ने बताया सरकार उठा रही है ये बड़ा कदम

नई दिल्ली। एजेंसी

बीते 2 महीने में कच्चा तेल ही नहीं बल्कि खाने के तेल के दाम भी आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया द्वारा तेल का निर्यात रोकने के बाद भारत में कीमतों की आग आम लोगों को झुलसा रही है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि रूस एवं यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत खाद्य तेलों के आयात के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। सीतारमण ने यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के एक कार्यक्रम में कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से भारत को खाद्य तेलों के आयात में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ''खाद्य तेल के आयात में कई बाधाएं हैं। हम खाद्य तेलों का आयात नहीं कर पा रहे हैं। हमें सूरजमुखी तेल मिल रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है।'' भारत यूक्रेन से बड़े पैमाने पर सूरजमुखी तेल का आयात करता रहा है लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सीतारमण ने कहा, ''ऐसी स्थिति में हम कई दूसरे बाजारों से खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं और कुछ नए बाजारों पर भी हमारी नजर है।'' इसके साथ ही उन्होंने घरेलू कारोबारियों से इस मौके का फायदा उठाते हुए तेल निर्यात की संभावनाओं पर गौर करने को कहा। उन्होंने कहा, ''उद्योगपतियों को हरेक चुनौती को अवसर में बदलने का मौका देखना चाहिए। केंद्र सरकार अपना समर्थन देने के लिए हमेशा ही तैयार है।'' सीतारमण ने भारतीय उद्योगों से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में साझा उद्यम लगाने के लिए भागीदार तलाशने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ''इन दोनों देशों में साझा उद्यम साझेदार का चयन करने से घरेलू उद्यमियों के लिए अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी।'' भारत ने पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अधिकांश भारतीय उत्पादों को इन दोनों देशों में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।

उपभोक्ताओं के खरीद निर्णय को प्रभावित कर रही है भारत में वस्तुओं, सेवाओं की बढ़ती लागत : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत के ज्यादातर उपभोक्ता अगले एक साल में अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। सलाहकार कंपनी अर्नस्ट एंड यंग (ईवाई) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत उपभोक्ताओं के खरीद निर्णयों को प्रभावित कर रही है। भारत के लिए ईवाई फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स के नौवें संस्करण के निष्कर्षों में कहा गया है कि बढ़ती जीवन लागत के प्रबंधन के बारे में अनिश्चितता की वजह से 80 प्रतिशत लोग अधिक बचत कर रहे हैं। यह सर्वे भारतीय उपभोक्ताओं के 'सकारात्मक दृष्टिकोण' की पुष्टि करता है क्योंकि 77 प्रतिशत लोगों को अगले एक साल में अपनी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उनके वैश्विक समकक्षों से बेहतर है। वैश्विक स्तर पर ऐसी राय जताने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 48 प्रतिशत है। रिपोर्ट कहती है, ''फरवरी, 2022 में 1,000 से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं पर किए गए सर्वे के मुताबिक, अधिकांश उपभोक्ताओं ने वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है।'' ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यह स्थिति निम्न आय वालों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ऐसे लोगों की संख्या 72 प्रतिशत है। उसके बाद उच्च-आय वर्ग के 60 प्रतिशत मध्यम-आय वर्ग के 58 प्रतिशत उपभोक्ता इससे प्रभावित हैं।

कोयले के ऊंचे आयात से डिस्कॉम की आपूर्ति लागत 4.5-5 प्रतिशत बढ़ेगी : इक्रा

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार के कोयला आयात बढ़ाकर बिजली आपूर्ति की कमी को दूर करने के उपायों से 2022-23 में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम की आपूर्ति लागत में 4.5-5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को यह अनुमान लगाया है। इक्रा ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने पांच मई को विद्युत अधिनियम की धारा-11 के तहत एक निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता पर परिचालन करें।

इस निर्देश के मुताबिक, घरेलू कोयले पर आधारित सभी राज्यों और बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) को अपनी ईंधन जरूरत का कम से कम 10 प्रतिशत आयात के जरिये पूरा करना होगा। उन्हें आयातित कोयले का घरेलू कोयले में मिश्रण कर बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना होगा।

मंत्रालय का यह निर्देश 31 अक्टूबर, 2022 तक मान्य है

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग्स) गिरीशकुमार कदम ने कहा कि अप्रैल और मई, 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 17.6 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पारा चढ़ने के साथ जहां बिजली की मांग बढ़ी है वहीं घरेलू स्तर पर कोयले की आपूर्ति में कमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके दाम चढ़ने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है।

दूध की पन्नियों, प्लास्टिक की बोतलों से बनाया जा सकेगा प्लाइवुड

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

दूध की पन्नियां, प्लास्टिक बोतल, खिलौने व प्लास्टिक के अन्य कचरे से प्लाइवुड बनाया जा सकेगा। यह लकड़ी के प्लाइवुड से ज्यादा मजबूत होगा। पानी का भी इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन लागत भी लकड़ी से तैयार किए जाने वाले प्लाइवुड के मुकाबले 10 प्रतिशत तक कम होगी। इसे बनाने की तकनीक भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के रसायन शास्त्र विभाग ने विकसित की है। यह तकनीक पर्यावरण के दुश्मन बने प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। मैनिट में केमिस्ट्री की विभागाध्यक्ष डा. सविता दीक्षित ने बताया इन प्लास्टिक कचरों से ऐसा प्लाइवुड तैयार किया है, जो लकड़ी का विकल्प हो सकता है। उनके अनुसार जिस तरह से वातावरण में कार्बन के तत्व बढ़ रहे हैं। पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे दूध की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें और टूटे-फूटे प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल कर हम प्लाइवुड बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक पालीमर कंपोजिट तैयार किया है। इस शोध का प्रकाशन अमेरिकी जर्नल एससीआइ में किया जा चुका है। उनके इस शोध का पेंटेंट भी मैनिट ने करा लिया है।

दो साल तक शोध के बाद मिली सफलता

डा. दीक्षित के अनुसार लगभग दो साल में यह शोध पूरा हुआ है। लगभग हर घर से रोज दूध की थैलियां, पालीथिन, पानी की बोतलें आदि निकलती हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। नतीजा ये सालों तक वातावरण में यूं ही पड़े रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक के कुछ अन्य सामान भी हैं। अब इस तकनीक से प्लाइवुड भी बनाया जा सकता है जो हमारे लिए उपयोगी होगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। डा.सविता ने अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट से प्लाइवुड से 500 सैंपल बनाए हैं। इन्हीं में दूध की थैली और अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट से बना प्लाइवुड भी शामिल है।

प्लाइवुड का टेंसाइल स्ट्रेंथ 20 एमपी है

डा. दीक्षित ने बताया कि यह लकड़ी के प्लाइवुड से ज्यादा मजबूत और सस्ता भी होगा। इसकी मजबूती (टेंसाइल स्ट्रेंथ) 20 मेगा पास्कल है। इसे लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका दोबारा उपयोग भी नए सिरे से प्लाइवुड व अन्य उत्पाद बनाने में हो सकता है।

इन चीजों को मिलाकर बनता है मजबूत प्लाइवुड

उन्होंने बताया कि इसे बनाने में एलडीपीई (कम घनत्व वाले पालीइथायलीन) जैसे प्लास्टिक की पतली पालीथिन, खाद्य पदार्थों की थैली, दूध की थैली, एचडीपीई (उच्च घनत्व पालीइथायलीन) जैसे प्लास्टिक की बोतलें, खिलौने, प्लास्टिक की टूटी बाल्टी के साथ-साथ अन्य प्लास्टिक के कचरे, नारियल का जूट, पराली, दवाओं की स्ट्रिप सहित कुछ रसायनों का उपयोग किया है।

कोल इंडिया ने पिछले तीन साल में सीएसआर गतिविधियों पर 1,600 करोड़ रुपये खर्च किए

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पिछले तीन वर्षों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं पर 1,600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। कंपनी की एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया का सीएसआर पर खर्च के लिए तय लक्ष्य 1,284 करोड़ रुपये था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) ने विज्ञप्ति में कहा, ''पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल ने सीएसआर गतिविधियों पर 1,600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।'' साथ ही, कोविड-19 महामारी के कठिन समय में सीआईएल ने देशभर में महामारी से लड़ने में मदद के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे। सीआईएल के निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन के मुताबिक, कोल इंडिया सीएसआर कार्यों पर खर्च करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सीआईएल ने अपने सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत से अधिक 'स्वास्थ्य' और 'स्वच्छता' क्षेत्र पर खर्च किया है। इसके अलावा, कंपनी ने 10,000 से अधिक युवाओं को 'रोजगार कौशल' प्रदान किया है। वर्तमान में, सीआईएल देश के आठ राज्यों के 34 जिलों में अपनी सीएसआर गतिविधियों का संचालन करती है। कोल इंडिया का घरेलू कोयला उत्पादन में भी 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

ब्रिटेन ने ईयू के साथ ब्रेक्सिट समझौते को फिर से तय करने की धमकी दी

लंदन। एजेंसी

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच बुधवार को ब्रेक्जिट को लेकर फिर ठन गई। ब्रिटेन ने ईयू के साथ अपने व्यापार समझौते के कुछ हिस्सों को खत्म करने की धमकी दी है। ब्रिटेन का कहना है कि ये नियम उत्तरी आयरलैंड में नई सरकार के गठन को बाधित कर रहे हैं। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि अगर सरकार ईयू के साथ समझौता नहीं कर पाती है तो सरकार ''कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।'' दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर फिर से बातचीत करने का ''कोई विकल्प नहीं है।'' नियमों को एकतरफा तरीके से बदलने के लिए ब्रिटेन द्वारा उठाया गया कोई भी कदम दोनों पक्षों के बीच कानूनी कार्रवाई और व्यापार युद्ध को बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटेन का एकमात्र हिस्सा है, जो यूरोपीय संघ के साथ सीमा साझा करता है। उत्तरी आयरलैंड के सबसे बड़े राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) ने सोमवार को गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह तब तक ऐसा नहीं करेगा, जब तक कि ब्रेक्जिट के बाद की सीमा शुल्क व्यवस्था पर उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती।

ट्राई ने कहा, 27.5-28.5 गीगाहट्र्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर डॉट करेगा निर्णय

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को कहा कि आईएमटी/ 5जी सेवाओं के लिए 27.5-28.5 गीगाहट्र्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज आवंटित या उसकी नीलामी करने के बारे में दूरसंचार विभाग को फैसला करना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3,300-3,670 मेगाहट्र्ज और 24.25-27.5 गीगाहट्र्ज बैंड के लिए निर्धारित अलग-अलग बैंड विशेष के लिए न्यूनतम रोलआउट दायित्वों पर अपने सिफारिशों का बचाव किया। दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा न्यूनतम रोलआउट दायित्वों को 3,300-3,670 मेगाहट्र्ज बैंड और 24.25-27.5 गीगाहट्र्ज बैंड पर संयुक्त तरीके से लागू करने की बात कहने पर ट्राई ने तर्क दिया कि इन बैंडों की नीलामी एक साथ नहीं, बल्कि अलग से की जाएगी। ट्राई ने कहा कि इन दोनों बैंडों की तकनीकी विशेषताएं काफी अलग हैं और इन स्पेक्ट्रम बैंडों के उपयोग के मामले भी अलग होने की संभावना है।

रूसी LNG से दुनिया ने किया किनारा, तो मिलने लगा डिस्काउंट

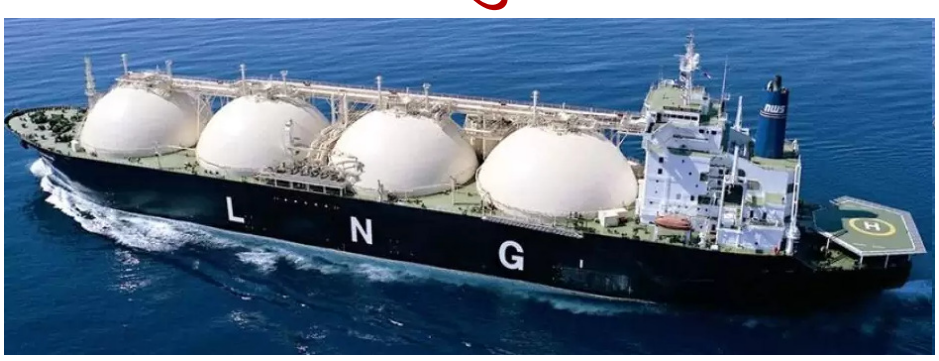

भारतीय ग्राहक उठा रहे पूरा-पूरा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अधिकांश स्पॉट बायर्स ने रूसी थ्ज्ञ से किनारा कर लिया है। इसका फायदा भारत के लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी थ्ज्ञ इंपोर्टर उठा रहे हैं। भारतीय ग्राहक रूस से अतिरिक्त मात्रा में छूट पर एलएनजी की खरीद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले ट्रेडर्स का कहना है कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और गेल इंडिया लिमिटेड सहित कुछ कंपनियों ने हाल ही में रूस से कई एलएनजी स्पॉट शिपमेंट, मौजूदा बाजार दरों से कम कीमत पर खरीदे हैं। जब तक रूसी ईंधन प्रतिद्वंद्वी सप्लायर्स की तुलना में सस्ता रहेगा, तब तक वे और ज्यादा खरीद कर सकते हैं।

भारत को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अपने एलएनजी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन अब प्रचंड गर्मी और चल रहे ब्लैकआउट देश की यूटिलिटीज को टॉप अप के तौर पर स्पॉट शिपमेंट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उर्वरक क्षेत्र में भी गैस की मांग बढ़ने के साथ, कुछ आयातक रियायती रूसी शिपमेंट को तेज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूसी एलएनजी शिपमेंट, भारतीय फर्म्स द्वारा हाल ही के स्पॉट टेंडर के माध्यम से खरीदे गए थे, क्योंकि उन कार्गो को अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में कम कीमत पर ऑफर किया गया था। भारत के बाहर कुछ एलएनजी आयातक, आपूर्तिकर्ताओं को खरीद टेंडर्स में रूसी-मूल के शिपमेंट की पेशकश करने की अनुमति देते हैं।

भारत, रूसी ईंधन के लिए अंतिम उपाय

भारत रूसी तेल पर अधिक छूट की मांग कर रहा है और रूसी ईंधन के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में उभरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण बाकी दुनिया ने रूस से दूरी बना ली है। एलएनजी पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं हैं, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया सहित शीर्ष खरीदारों ने भविष्य के दंड या प्रतिष्ठा की क्षति से बचने के लिए खरीदारी रोक दी है। पेट्रो चाइना कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वह किसी भी रियायती रूसी स्पॉट की आपूर्ति की मांग नहीं कर रही है। हालांकि अतिरिक्त स्पॉट एलएनजी शिपमेंट्स से बचा जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अधिकांश रूसी डिलीवरीज, अभी भी दुनिया भर के ग्राहकों द्वारा स्वीकार की जा रही हैं।

कामधेनु लिमिटेड ने इंदौर, मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति मजबूत की

इंदौर में चैनल पार्टनर्स मीट का आयोजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े निर्माता और खुदरा क्षेत्र में ब्रांडेड टीएमटी बार्स के विक्रेता कामधेनु लिमिटेड ने इंदौर, मध्य प्रदेश में टीएमटी बार्स की अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी व्यावसायिक रणनीति की घोषणा की है। रणनीति के हिस्से के रूप में, कंपनी ने आज स्थानीय डीलरों के लिए एक चैनल पार्टनर्स मीट का आयोजन किया है और शहर के लिए कंपनी की विकास योजना के बारे में चर्चा की है। बैठक में लगभग 100 डीलरों ने भाग लिया जहां श्री एस.बी. शर्मा सीनियर जी.एम. (विपणन) कामधेनु ने डीलरों के प्रयासों को सराहा।

इसके अलावा, कंपनी इंदौर में अपने प्रीमियम ब्रांड 'कामधेनु नेक्स्ट' - अगली पीढ़ी के हाई-एंड इंटरलॉक स्टील टीएमटी बार की उत्पादन क्षमता को अगले 20 महीनों में 48000 मीट्रिक टन प्रीमियम टीएमटी बार से बढ़ाकर 100000 मीट्रिक टन करने की भी योजना बना रही है।

श्री एस.बी. शर्मा (सीनियर जीएम मार्केटिंग), कामधेनु लिमिटेड ने कहा, कामधेनु के विकास के लिए इंदौर एक महत्वपूर्ण बाजार है जो विशाल बुनियादी ढांचे और निर्माण के अवसर प्रदान करता है। कामधेनु में, हम उन सभी के लिए विकास में विश्वास करते हैं जहां चैनल पार्टनर और डीलर परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

कामधेनु नेक्स्ट की विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई डबल रिब, थकान शक्ति और लचीलापन इसे सामान्य स्टील बार से बहुत बेहतर बनाती है। 'कामधेनु नेक्स्ट' का विशिष्ट डिजाइन कंक्रीट मिश्रण के साथ बेहतर इंटरलॉक के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है, जिससे संरचना को अधिक शक्ति मिलती है। इस स्टील बार पर दो कोणीय पसलियां स्टील और कंक्रीट के बीच इंटरलॉक ताकत को बढ़ाती हैं जिससे उन संरचनाओं को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान होती है जो भूकंपीय, गतिशील प्रभाव आदि जैसे अप्रत्याशित बलों के अधीन हैं। यह पुलों, फ्लाईओवर, बांधों जैसे कंक्रीट प्रबलित संरचनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। थर्मल और हाइडल प्लांट, औद्योगिक टावर, स्काईलाइन बिल्डिंग, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म। उन्होंने आगे कहा कि 'कामधेनु नेक्स्ट' कामधेनु में प्रचलित विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं विकास और अभिनव उत्पाद विकास का एक उत्पाद है। 2.5 गुना मजबूत कंक्रीट-स्टील इंटरलॉक के साथ, कामधेनुनेक्स्ट ऐसी विशेषताएं प्रदान करता है, जो इंजीनियर सुदृढ़ीकरण संरचनाओं और स्मार्ट वास्तुशिल्प अवधारणाओं में नए युग की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। कामधेनु इस क्षेत्र में उभरती जरूरतों को पूरा करने और बाजार में तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों के लिए सामर्थ्य में एक बेंचमार्क स्थापित करने के लिए विश्व स्तर के उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अर्धसैनिक बलों की 107 कैंटीन में खादी उत्पादों की बिक्री शुरू, शाह ने किया शुभारंभ

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 107 कैंटीन में खादी उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इन कैंटीन में खादी उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कहा कि देशभर में अर्धसैनिक बलों की सभी कैंटीन जल्द ही खादी उत्पादों की बिक्री शुरू कर देंगी। उन्होंने असम के तामुलपुर में बीएसएफ की केंद्रीय कार्यशाला और स्टोर के शिलान्यास समारोह के मौके यह घोषणा की।

शाह ने कहा, ''मुझे खुशी है कि अर्धसैनिक बलों की 107 कैंटीनों में खादी उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है और जल्द ही देशभर में अर्धसैनिक बलों की सभी कैंटीनों में खादी उत्पाद उपलब्ध होंगे।'' उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा संचालित हनी मिशन, कुम्हार सशक्तीकरण योजना, चमड़ा और बढ़ई सशक्तीकरण जैसी योजनाओं में असम के बोडोलैंड में स्थायी रोजगार पैदा करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, ''अगर केवीआईसी लोगों को अपनी स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से इससे बोडोलैंड में बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सकता है।''

इससे पहले गृह मंत्री ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में केवीआईसी के जरिये अधिकतम स्वदेशी उत्पादों को बेचना अनिवार्य कर दिया था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज, सूती तौलिए, शहद, कच्ची घानी सरसों का तेल, अगरबत्ती, दलिया, पापड़, अचार, आंवला सहित 32 उत्पादों की आपूर्ति दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्यों में स्थित कैंटीनों में की जाएगी।

क्रिप्टो निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका, 28 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी में जीएसटी परिषद

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में बजट वाले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो असेट पर 30 फीसदी का टैक्स और फीसदी टीडीएस लगाकर निवेशकों को झटका दिया था, वहीं अब इन्हें एक और झटका देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, ये तैयारी है बिटक्वाइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने की और जीएसटी परिषद इन डिजिटल करेंसियों पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने पर विचार कर रही है।

कैसिनो-लॉटरी के बराबर जीएसटी

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में क्रिप्टो निवेशकों को एक और परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। 30 फीसदी टैक्स के बाद अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भी क्रिप्टोकरेंसी पर भारी भरकम टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि यह कैसीनो, सट्टेबाजी और लॉटरी पर वसूले जाने वाले वर्तमान जीएसटी के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन, अगर बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो बिक्री और खरीद के साथ-साथ क्रिप्टो माइनिंग जैसी सेवाओं पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी वसूले जाने की पूरी संभावना है।

पहले से लागू टैक्स से अलग

यहां बता दें कि यह 28 फीसदी जीएसटी क्रिप्टो संपत्ति के लेन-देन से होने वाली आय पर पहले से लगने वाले 30 फीसदी टैक्स के अतिरिक्त होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान इन लेनदेन से आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी, इसके साथ ही ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी की दर से टीडीएस को नियम भी लागू किया था। यह नियम बीती एक अप्रैल 2022 से लागू किया जा चुका है।

भारत, ओमान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को बैठक करेंगे

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और ओमान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को यहां बैठक करेंगे। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसेफ की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 10-14 मई तक भारत में रहेगा। बयान के मुताबिक 48 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य, दवा उद्योग (फार्मास्यूटिकल्स), खनन, पर्यटन, ऊर्जा, शिपिंग, दूरसंचार और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इस दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी 11 मई को होने वाली भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) के 10वें सत्र में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2021-22 में 82 प्रतिशत बढ़कर 9.94 अरब डॉलर हो गया है।

शिपिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड ने गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की योजना में बदलाव को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निदेशक मंडल ने कंपनी की गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है। इन गैर-प्रमुख संपत्तियों को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लि. (एससीआईएलएएल) को स्थानांतरित किया जाएगा।

रणनीतिक बिक्री प्रक्रिया के तहत सरकार शिपिंग हाउस और प्रशिक्षण संस्थान सहित एससीआई की कुछ गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग कर रही है। कंपनी ने सोमवार को बीएसई को भेजी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने गैर-प्रमुख संपत्तियों को एससीआईएलएएल में स्थानांतरित करने की योजना में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों पर पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा दीपम विभाग की मंजूरी ली जाएगी। अधिकारी ने कहा, ''गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया काफी समय लेती है। हम तीन-चार माह में वित्तीय बोलियां मंगाने की स्थिति में होंगे।'' एससीआई के निदेशक मंडल ने कंपनी की गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की योजना को पिछले साल अगस्त में मंजूरी दी थी। उसके बाद नवंबर, 2021 में एससीआईएलएएल का गठन किया गया था।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल, 2022 में एससीआई को गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा है।

पिछले साल मार्च में सरकार को शिपिंग कॉरपोरेशन के निजीकरण के लिए कई बोलियां मिली थीं। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने दिसंबर, 2020 में कंपनी में सरकार की समूची 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए थे। हिस्सेदारी बिक्री के साथ ही कंपनी का प्रबंधन भी स्थानांतरित किया जाना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2020 में शिपिंग कॉरपोरेशन के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी। शिपिंग कॉरपोरेशन का निजीकरण अब चालू वित्त वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

News यू केन USE

सरकार ने तांबे की ट्यूब, पाइप पर प्रतिपूर्ति शुल्क लगाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से आयातित तांबे की ट्यूब और पाइप पर पांच साल के लिए प्रतिपूर्ति शुल्क लगाया है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने मामले को खुद संज्ञान में लेकर जांच की और उसकी सिफारिशों के आधार पर यह कार्रवाई हुई। शुल्क लगाने का मकसद घरेलू कंपनियों को इन देशों के सस्ते आयात से संरक्षण देना है। राजस्व विभाग ने 28 अप्रैल को कहा, ''इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपूर्ति शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच साल के लिए है, जो भारतीय मुद्रा में देय होगा।'' लगाया गया शुल्क सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य के 2.13 प्रतिशत से 14.76 प्रतिशत के बीच है। सीआईएफ मूल्य माल का वास्तविक मूल्य है, जिस पर उनका निर्यात किया जाता है। डीजीटीआर द्वारा शुल्क लगाने की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय इस संबंध में अंतिम निर्णय लेता है। प्रतिपूर्ति शुल्क घरेलू व्यापार एवं बाजार की रक्षा के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

बंदरगाह मंत्रालय ने तनावग्रस्त संपत्तियों के पुनरुद्धार के दिशानिर्देश तय किए

नयी दिल्ली। एजेंसी

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली अटकी परियोजनाओं के शीघ्र समाधान के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। एक आधिकारिक दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य दबाव वाली संपत्तियों की श्रेणी में आने वाली परियोजनाओं का पुनरुद्धार करना है। इन दिशानिर्देशों से मुकदमेबाजी में फंसे मामलों के समाधान का भी रास्ता खुलेगा। दस्तावेज के अनुसार, बंदरगाह संपत्तियों को दोबारा बोली लगाकर फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा। इससे करीब 2.7 करोड़ टन की कार्गो रखरखाव क्षमता को इस्तेमाल के लिए 'खोला' जा सकेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि इससे संभावित निवेशकों के लिए कारोबार के बेहतर अवसर पैदा होंगे और बंदरगाह प्राधिकरण को राजस्व मिलना शुरू होगा। इसके मुताबिक, अटकी परियोजनाओं के त्वरित समाधान से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, सब्सिडी से अलग हटकर सोचना चाहिए : सीआईआई अध्यक्ष

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष टी वी नरेंद्रन ने बुधवार को कहा कि भारतीय उद्योग को प्रोत्साहनों और सब्सिडी से हटकर सोचना चाहिए और प्रतिस्पर्धा और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्रन ने 'बीइंग फ्यूचर रेडी बिजनेस समिट-2022' में कहा कि एक जिम्मेदार और जागरूक उद्योग को देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं से परे सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का फिर से आकलन उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में खुद को और अधिक मजबूती से पेश करने के साथ वैश्विक स्तर पर कारोबार का विस्तार करने का अवसर भी देता है। सीआईआई के अध्यक्ष ने कहा, ''हमें जोखिम नहीं उठाने की मानसिकता से हटकर सोचना चाहिए और सभी बाजारों और क्षेत्रों में कारोबार की संभावना तलाशनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''हमारे प्रमुख बाजार भागीदारों के साथ कई नए मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं जो हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अपार अवसर खोलेंगे।''

जेट एयरवेज को मुंबई स्थित कार्यालय खाली करने का निर्देश

नयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दोबारा परिचालन शुरू करने की जद्दोजहद में लगी एयरलाइन जेट एयरवेज को मुंबई के मैक स्टार मार्केटिंग परिसर में स्थित अपना कार्यालय खाली करने को कहा है। एनसीएलएटी की तीन-सदस्यीय पीठ ने गत छह मई को पारित इस आदेश में कहा कि एयरलाइन जिस समय कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही थी, उस समय का कोई भी मासिक शुल्क मैक स्टार मार्केटिंग को नहीं दिया जाएगा। कर्ज के बोझ तले दबने के बाद जेट एयरवेज को अप्रैल, 2019 में अपना परिचालन बंद करना पड़ा था। उसी साल जून में उसके खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। मैक स्टार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इस अपील में कहा गया था कि एनसीएलटी ने परिसर में जेट एयरवेज के बने रहने को दोषपूर्ण ढंग से सही ठहराया था। इस पर एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज को परिसर में मौजूद अपना कार्यालय 15 दिनों के भीतर खाली करने को कहा। लेकिन इसी के साथ कर्ज समाधान अवधि के दौरान मासिक शुल्क की देनदारी से भी राहत दी।

भारत ने टैरिफ-दर कोटा के तहत अमेरिका को अतिरिक्त 2,051 टन कच्ची चीनी निर्यात की अनुमति दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने अमेरिका को 30 सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाले अमेरिकी वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 2,051 टन कच्ची चीनी के अतिरिक्त निर्यात की अनुमति दी है। डीजीएफटी ने यह जानकारी दी। टीआरक्यू निर्यात की मात्रा का एक कोटा है जो अपेक्षाकृत कम शुल्क पर अमेरिका में भेजा जाता है। कोटा पूरा होने के बाद, अतिरिक्त आयात पर अधिक शुल्क लागू होता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ''30 सितंबर, 2022 तक टीआरक्यू के तहत अमेरिका को निर्यात के लिए 2,051 टन कच्ची चीनी की अतिरिक्त मात्रा अधिसूचित की गई है।'' इसमें कहा गया है कि इस मात्रा को मिलाकर, अमेरिकी वित्त वर्ष 2022 के दौरान टीआरक्यू के तहत अमेरिका को कुल चीनी निर्यात 10,475 टन का हो जायेगा। भारत, चीनी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यूरोपीय संघ के साथ भी चीनी निर्यात के लिए एक तरजीही कोटा व्यवस्था है।

गेल मध्य प्रदेश के गुना में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड मध्य प्रदेश के गुना में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र लगाएगी। इसके लिए कंपनी एक प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, जो भारत में इस तरह के सबसे बड़े संयंत्रों में एक होगा। इस संयंत्र से 2023 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। भारत की सबसे बड़ी गैस विपणन कंपनी ने बयान में कहा कि उसने पीईएम-आधारित परियोजना लगाने का ठेका दिया है, जिसके तहत प्रतिदिन 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन (लगभग 10 मेगावाट क्षमता) का उत्पादन किया जाएगा। इसे प्राकृतिक गैस में मिलाकर उद्योगों को आपूर्ति की जाएगी। बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप गेल ने भारत में सबसे बड़े पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर में से एक को स्थापित करने के लिए ठेका दिया है। यह परियोजना गुना जिले में गेल के विजयपुर परिसर में स्थापित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि संयंत्र से नवंबर, 2023 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने परियोजना की लागत और अन्य विवरण नहीं दिया।

कतर सौदे का नवीनीकरण करने के लिए कीमत में कटौती चाहती है पेट्रोनेट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत की प्रमुख गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर सौदे का नवीनीकरण करने के लिए कीमत घटाने की मांग की है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अक्षय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि दीर्घकालिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात सौदे का 2028 से आगे नवीनीकरण करने के लिए कतर गैस को कीमत कम करनी चाहिए।

कंपनी देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में 7.5 लाख से 10 लाख टन एलएनजी के लिए सौदा करना चाहती है। खासतौर से शहरी गैस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी एलएनजी के लिए सौदा करना चाहती है। सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कतर भारत को प्रतिवर्ष 75 लाख टन एलएनजी की बिक्री करता है। ये बिक्री मौजूदा ब्रेंट कीमत के 12.67 प्रतिशत और 0.52 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) के आधार पर की जाती है। (यदि तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल है तो एलएनजी की कीमत 13.19 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू होगी।) पेट्रोनेट इस कीमत के मुकाबले थोड़े से बदलाव पर अतिरिक्त 10 लाख टन एलएनजी भी खरीदती है। प्रति वर्ष 85 लाख टन का करार 2028 में खत्म हो रहा है।

सिंह ने आगे कहा, ''उन्होंने (कतर गैस) बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान सहित हमारे पड़ोसी देशों के साथ निचली दरों पर (12.67 प्रतिशत से अधिक) अनुबंध किया है। हमें उम्मीद है कि उन स्तरों पर दीर्घकालिक सौदे का नवीनीकरण किया जाएगा।'' उन्होंने कहा, ''हम उनके साथ बेहद गंभीरता से बेहतर कीमत के लिए बातचीत कर रहे हैं।'' उन्होंने संकेत दिया कि पेट्रोनेट मौजूदा 85 लाख टन से अधिक मात्रा के लिए अनुबंध कर सकती है

अमेरिकी सदन में यूक्रेन के लिए 40 अरब डॉलर के नये सहायता पैकेज को मंजूरी

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिकी सदन के सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडन के शुरुआती अनुरोध को बल प्रदान करते हुए यूक्रेन की मदद के लिए मंगलवार को 40 अरब डॉलर के नये सहायता पैकेज को मंजूरी दी। यह यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तीन महीने से जारी युद्ध के खिलाफ द्विदलीय प्रतिबद्धता का संकेत है। विधेयक 57 के मुकाबले 368 मतों के अंतर से पारित हुआ, जो अप्रैल में बाइडन की ओर से अनुरोध की गई राशि से सात अरब डॉलर अधिक है। विधेयक में यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता देने, क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद करने, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन द्वारा भेजे गए हथियारों की भरपाई करने या बदलने का भी प्रावधान है। विधेयक में युद्ध के कारण यूक्रेन के कई फसलों के बर्बाद होने के कारण वैश्विक खाद्य कमी को दूर करने के लिए पांच अरब डॉलर की मदद प्रदान करने का प्रावधान है।

वहीं, यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत के लिए बाइडन प्रशासन की उम्मीदवार ब्रिजेट ब्रिंक ने मंगलवार को सांसदों से वादा किया कि वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को ''रणनीतिक रूप से विफल'' करने के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वह कूटनीति के बजाय यूक्रेन की सेना के लिए पश्चिमी देशों से भेजी जा रही हथियार की खेप के समन्वय पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। ब्रिंक ने अपने 25 साल के राजनयिक करियर का अधिकांश समय पूर्व सोवियत गणराज्यों में बिताया है। उन्होंने सीनेट की विदेश संबंधी समिति के सदस्यों से बात की। ब्रिंक के नाम पर सीनेट की पुष्टि होने की उम्मीद है।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ष 2019 में राजदूत मेरी योवानोविच को अचानक बाहर करने के बाद से यह पद खाली है। वह बाद में ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही में पहली प्रमुख व्यक्ति बनीं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडन और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने मंगलवार को ओवल कार्यालय में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ मित्र देशों की एकता दिखाने के इरादे से मुलाकात की। द्राघी ने कहा कि नेताओं को ''संघर्षविराम लाने और फिर से कुछ विश्वसनीय वार्ता शुरू करने की संभावना'' की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा

कि ''इटली और यूरोप में अब लोग इन नरसंहारों और हिंसा तथा कत्लेआम को समाप्त करना चाहते हैं।'' बाइडन ने हालांकि द्राघी की टिप्पणियों को नहीं दोहराया

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों को अब इस बिंदु पर वार्ता शुरू होने का संदेह है। नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक एवरिल हेन्स ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ''लंबे समय तक संघर्ष'' के लिए तैयार हैं।

टाटा मोटर्स ने उतारी 'नेक्सन ईवी मैक्स', कीमत 17.74 लाख रुपये से शुरू

नयी दिल्ली। एजेंसी

टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) श्रृंखला का विस्तार करते हुए नेक्सन ईवी का नया संस्करण 'नेक्सन ईवी मैक्स' बाजार में उतारा है। इसकी शोरूम कीमत 17.74 लाख रुपये से 19.24 लाख रुपये के बीच है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। नेक्सन ईवी मैक्स, 40.5 केडब्ल्यूएच लिथियम-आयन बैटरी पैक से लैस है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी क्षमता 'नेक्सन ईवी' की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। टाटा मोटर्स ने इस वाहन को दो ट्रिम्स 'नेक्सन ईवी मैक्स एक्सजेड्ड' और 'नेक्सन ईवी मैक्स एक्सजेड्ड लक्स' में पेश किया है। पेश किया है। 3.3 केडब्ल्यू चार्जर के साथ एक्सजेड्ड ट्रिम की शोरूम कीमत 17.74 लाख रुपये है जबकि 7.2 केडब्ल्यू फास्ट चार्जर वाले समान ट्रिम की शोरूम कीमत 18.24 लाख रुपये है। इसी तरह 3.3 केडब्ल्यू के एक्सजेड्ड लक्स ट्रिम की कीमत 18.74 लाख रुपये और 7.2 केडब्ल्यू चार्जर वाले इसी संस्करण का दाम 19.24 लाख रुपये है। टाटा मोटर्स ने 2020 में ईवी क्षेत्र में कदम रखने के बाद से 25,000 से अधिक बिजलीचालित वाहन बेचे हैं। इनमें से 19,000 नेक्सन ईवी हैं। टाटा मोटर्स वर्तमान में घरेलू बाजार में तीन इलेक्ट्रिक मॉडल... नेक्सन ईवी, टिगोर ईवी और एक्सप्रेस-टी ईवी बेचती है।

महिला सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध आईएचसीएल ने लांच किया 'शी रिमेन्स द ताज'

महिला मुसाफिरों के लिए पेश की कस्टमाइज़्ड ऑफरिंग

2025 तक 25 प्रतिशत महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटेलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने 'शी रिमेन्स द ताज' को लांच किया जो की महिला केन्द्रित गतिविधियों का एक समग्र फ्रेमवर्क है जो अतिथि, कर्मचारी, सहभागी व समुदाय समेत सभी स्टेकहोल्डरों के लिए है। यह फ्रेमवर्क दुनिया भर में कंपनी के होटलों में महिला मुसाफिरों के लिए बेहतर अनुभव को मुमकिन बनाएगा। आईएचसीएल ने यह भी बताया की 2025 तक कंपनी का लक्ष्य अपने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने का है, तथा कंपनी महिलाओं की अगुआई वाले कारोबारों और महिला साझीदरों को भी समर्थन देगी।

इस मौके पर आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पुनीत छटवाल ने कहा, 'आईएचसीएल को संगठन के भीतर व बाहर दोनों जगह महिलाओं के मुद्दों पर काम करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। महिला ग्राहकों के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को देखते हुए 'शी रिमेन्स द ताज' ने पुनः दोहराया है की वह यात्रियों के लिए ग्राहक-केन्द्रित अनुभवों की रचना हेतु प्रतिबद्ध है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम ऐसी गतिविधियों और नीतियों की श्रृंखला शुरु करेंगे जिनसे हमारी वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में इज़ाफ़ा होगा। समुदाय को केन्द्र में रखते हुए आईएचसीएल व्यापक स्तर पर आर्थिक अवसरों वृद्धि जारी रखेगी।' गहन अनुसंधान के आधार पर महिला यात्रियों को ध्यान में रखते हुए काफी विकास किया गया है जिसमें उच्च स्तर की गोपनीयता, सुरक्षा, सुविधाएं व ठहरने संबंधी पेशकशें आदि शामिल हैं। लीडरशिप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्रतिबद्ध आईएचसीएल ने अपने आगामी होटलों में महिला कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है।

रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की क्लैम सेटलमेंट में उत्कृष्टता

शुद्ध लाभ में 30% की बढ़त के साथ मजबूत वृद्धि दर्ज की

मुंबई। एजेंसी

रिलायंस कैपिटल और जापान की निप्पॉन लाइफ के जॉइंट वेंचर, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को वर्ष की समाप्ति के लिए अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की घोषणा की। 31 मार्च, 2022 तक की प्रमुख परफॉर्मेंस में निम्न बिंदु शामिल हैं:वित्त वर्ष 22 में कंपनी की प्रबल परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करते हुए, श्री आशीष वोहरा, ईडी और सीईओ, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने कहा, 'वित्त वर्ष 22, महामारी की लगातार दूसरी और तीसरी लहर के प्रकोप के साथ कई चुनौतियों से गुज़रा है। हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, वितरकों, सेवा प्रदाताओं और उनके परिवारों से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं, जिसने हमारे प्रत्येक हितधारक को अधिकतम मूल्य प्रदान करने की हमारी यात्रा को सफल बनाया है।' श्री वोहरा ने आगे कहा कि आज के अस्थिर आर्थिक वातावरण में, लाइफ कवरेज के साथ-साथ फाइनेंशियल इंवेस्टमेंट्स की निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस को सराहा जा रहा है। इन ग्यारंटीज़ को टिकाऊ

श्री वोहरा ने आगे कहा कि आज के अस्थिर आर्थिक वातावरण में, लाइफ कवरेज के साथ-साथ फाइनेंशियल इंवेस्टमेंट्स की निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस को सराहा जा रहा है। इन ग्यारंटीज़ को टिकाऊ लॉन्ग-टर्म रिटर्न्स प्राप्त करने, ग्राहकों को उनके जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने और हमारे बिज़नेस मॉडल का आधार बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 22 में डेथ क्लैम्स, मैच्योरिटी और सर्वाइवल लाभ का 1,877 करोड़ रूपए भुगतान किया और वित्त वर्ष 22 के लिए 98.7इ का प्रभावशाली क्लैम्स सेटलमेंट रेश्यो प्राप्त किया, जो कि वित्त वर्ष 21 में 98.5इ था। कंपनी ने 9 कार्य दिवसों की औसत अवधि के भीतर 117 करोड़ रूपए के 3,517 कोविड संबंधित क्लैम्स का शीघ्र निपटान किया। श्री वोहरा ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा, 'डेथ क्लैम, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अंतिम परीक्षा है, और लाइफ इंश्योरर का यह 'धर्म' है कि वह ऐसे सभी क्लैम्स को गति और सटीकता के साथ पूरा करे। हम आने वाले समय में ग्राहकों के सभी क्लैम्स को पूरा करने के लिए 235इ सॉल्वेंसी (150इ की नियामक आवश्यकता के खिलाफ) पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध और वित्तीय रूप से स्थिर बने रहेंगे।

गुरुवार को एकादशीः श्रीकृष्ण ने बताया है इस संयोग का महत्व, इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी के साथ तुलसी पूजा से बढ़ती है सुख-समृद्धि

गुरुवार, 12 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य नाम के अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को एकादशियों के व्रत के बारे में बताया है।

पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत-उपवास और विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस दिन जल और दूध से भगवान विष्णु-लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। पीले फूलों से पूजा करें। इसके बाद विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु के अवतारों की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी पर बाल गोपाल को भी माखन-मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी पर सूर्यास्त के बाद श्रीहरि और तुलसी की पूजा करनी चाहिए।

तीन शुभ योग

मोहिनी एकादशी पर सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्रों से रवियोग बन रहा है। साथ ही उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होने से मातंग नाम का शुभ योग भी बन रहा है और हर्षण योग भी रहेगा। इन शुभ संयोग में एकादशी व्रत का संयोग कम ही बनता है। इन योगों में पूजा और व्रत का शुभ फल और बढ़ जाएगा। जिससे सुख और समृद्धि मिलेगी। वहीं इस दिन किए जलदान से कभी न खत्म होने वाला कई गुना पुण्य मिलेगा।

मोहिनी स्वरूप की पूजा का दिन

इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से अमृत को बचाने के लिए लिया था। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। साथ ही जाने-अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं।

त्रेता और द्वापर युग में भी हुआ ये व्रत

मोहिनी एकादशी व्रत करने से जाने-अनजाने में हुए हर तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। मोह बंधन और पाप खत्म हो जाते हैं। माता सीता की खोज करते समय भगवान श्रीराम ने भी इस व्रत को किया था। उनके बाद मुनि कौण्डिन्य के कहने पर धृष्टबुद्धि ने और श्रीकृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी ये व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से इन सभी को दुख और परेशानियों से मुक्ति मिली थी।

ऐसे कर सकते हैं तुलसी पूजन

मोहिनी एकादशी की शाम घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श न करें। पूजा में शालग्राम जी की प्रतिमा भी रखनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम जी को हार-फूल, वस्त्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। फलों का भोग लगाएं। तुलसी के सामने बैठकर तुलसी की माला से तुलसी मंत्र जाप करें। मंत्र जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। मंत्र- ऊँ श्री तुलस्यै विद्महे। विष्णु प्रियायै धीमहि। तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्।।

पीपल पूजाः वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं।

तुलसी पूजाः दूध और पानी से भगवान शालग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए जल में से थोड़ा सा खुद पीएं और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्रियों से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए।

एकादशी पर और कौन-कौन से शुभ काम करें

1. जरूरतमंद लोगों को अन्न और जल का दान करें।
2. गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें।
3. विष्णु मंदिर में जल, दूध और पंचामृत दान करें।
4. पानी में दूध मिलाकर सुबह जल्दी पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।
5. जरूरतमंद लोगों को मौसमी फलों का दान करें।

मोहिनी एकादशी के दिन गलती से भी न करें ये काम

■मोहिनी एकादशी या एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को न तोड़ें. ■एकादशी तिथि को बाल, मूंछ, दाढ़ी या नाखून आदि न काटें. ■जीवनसाथी के साथ नजदीक संबंध न रखें. ■मोहिनी एकादशी ही नहीं किसी भी एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें. ■मोहिनी एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें. ■किसी के लिए भी अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें.

अमृत के समान है गंगाजल, स्पर्श मात्र से ही मिलता है पुण्य

गंगाजल को अमृत तुल्य माना जाता है। गंगाजल की पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग गंगाजल हाथ में लेकर वचन लेते हैं और यदि व्यक्ति के अंतिम समय में मुख में गंगाजल की बूंद डाल दी जाएं तो माना जाता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गंगाजल का स्पर्श करने मात्र से कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर में गंगाजल होने से नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगाजल के स्पर्श मात्र से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। गंगाजल पूजनीय है, इसलिए हमेशा इसे मंदिर या पूजा स्थान में ही रखें। घर में यदि क्लेश की स्थिति रहती हो तो रोजाना सुबह स्नान-पूजन के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। बच्चे को बुरी नजर लगने पर उस पर गंगाजल छिड़कें। घर में बीमारियों का डेरा हो तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में पीतल के पात्र में गंगाजल भरकर रख दें। हर सोमवार भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें। हर शनिवार गंगाजल मिश्रित जल पीपल के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें। यदि रात में डरावने सपने आते हों तो सोने से पहले बिस्तर पर गंगाजल छिड़क लें। भगवान शिव गंगाजल अर्पित करने से अति प्रसन्न होते हैं। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो बुधवार के दिन भगवान श्रीगणेश की पूजा करें। साथ ही बच्चे के कमरे व स्टडी रूम में गंगाजल छिड़कें। यदि घर के लोगों में गुस्सा रहता हो तो उनके ऊपर गंगाजल छिड़कें। इससे मन को शांति मिलेगी। गंगाजल का नियमित सेवन करने से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बुद्धि तेज होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।

✍संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

तुलसी का ये टोटका पूरी करेगा हर मुराद, घर की अनबन से लेकर जेब की तंगी होगी दूर

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पवित्र माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। श्रहरि की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बिना तुलसी के श्रीविष्णु को भोग नहीं लगता। इस पौधे को घर में लगाने से सुख-समृद्धि का वास होता है। तुलसी के कई औषधीय गुण भी हैं। धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से जीवन नें सुख-शांति बनी रहती है। वहीं तुलसी को कुछ उपाय कर कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं तुलसी के चमत्कारी उपाय।

इस मंत्र से तुलसी पर चढ़ाएं जल

घर में अनबन, रोग या आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो तुलसी को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय मंत्र (महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते) का जाप करें।

इच्छा पूरी करने के लिए

अपनी इच्छा को सोचकर एक पीला धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं। अपनी मनोकामनाओं को बोल दें। साथ ही पीले धागे की 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी को पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इस धागे को निकालकर जल में बहा दें।

घर की नेगेटिविटी होगी दूर

तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इसलिए भगवान की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपाय को करने से हर इच्छा पूरी होगी। बस सोने से पहले अपने तकिए के नीचे पांच तुलसी के पत्ते रखकर सो जाएं। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूरी हो जाएगी।

धन की कमी नहीं रहेगी

सुबह के समय तुलसी के 4 पत्तियों को तोड़ लें। फिर पीतल के बर्तन में पानी डालकर भिगो दें। 24 घंटे पानी में रखने के बाद उस पानी के छींटें पूरे घर में छिड़क दें। ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़के। इस उपाय से आपकी किस्मत चमक जाएगी। घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी।

चांदी की ईंट के 7 प्रयोग आजमाएं, सुख-समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद पाएं

चांदी बहुत ही शीतल, सुंदर और शुभ धातु है... इसके कई प्रयोग हम विद्वान बताते हैं....आइए आज हम आपको चांदी की ईंट के फायदे बताते हैं...

1. सुख, शांति और समृद्धि के लिए घर की नींव में चांदी की ईंट लगवाएं।
2. रिश्तों में मधुरता के लिए घर में चांदी की ईंट रखें।
3. सुखी दाम्पत्य के लिए विवाह के समय चांदी की ईंट अपनी पत्नी को दें।

4.तिजोरी में चांदी की ईंट रखने से घर के धन में स्थिरता आती है।

5.सप्तम में राहु और लग्न में केतु हो तो-1-चांदी की ईंट बनवाकर घर के मंदिर में रखें।

6. एकादश भाव में शनि अशुभ फल दे रहा हो तो जातक को घर के इशान कोण में चांदी की ईंट रखनी चाहिए।

7.बच्चों के करियर में तरक्की के लिए चांदी की बहुत छोटी सी ईंट उसके पास या सिरहाने रखना चाहिए।

टाटा मोटर्स ने नए एस ईवी के साथ ई-कार्गो के क्षेत्र में परिवहन समाधान पेश

अमेज़न, बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट और उनके लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ साझेदारी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने नए, क्रांतिकारी एस ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) के लॉन्च के साथ स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने के अपने अभियान में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। एस ईवी कंपनी के बेहद लोकप्रिय वाहन, एस का इलेक्ट्रिक वर्जन है। कंपनी वास्तव में 17 साल के लंबे अंतराल के बाद फ्रेट मूवमेंट यानी माल की आवाजाही को पुनर्परिभाषित कर रही है। नई एस ईवी भारत का सबसे उन्नत, ज़ीरो-उत्सर्जन वाला चौपहिया छोटा वणिज्यिक वाहन (एससीवी) है। यह एक हरित एवं स्मार्ट परिवहन समाधान है जो शहर के भीतर तरह-तरह के इस्तेमाल के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। एस ईवी की पेशकश पर श्री एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस एवं टाटा मोटर्स ने कहा, 'ई-परिवहन एक ऐसा विचार है जिसका समय अब आ गया है। टाटा मोटर्स में, हम यात्री कारों, वाणिज्यिक वाहनों और जगुआर लैंड रोवर में इस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए तेजी से और व्यापक पैमाने के साथ बढ़ रहे हैं। मुझे आज खुशी है कि एस ईवी के लॉन्च के साथ हम ई-कार्गो परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। टाटा एस भारत का अब तक का सबसे सफल वाणिज्यिक वाहन है। यह परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है और इतने सालों में लाखों कामयाब उद्यमी बनाए। तकनीकी रूप से उन्नत, स्वच्छ और स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदान करके अपनी धरोहर को आगे बढ़ाएगा। मैं वाणिज्यिक वाहनों के विद्युतीकरण को लेकर बहुत उत्साहित हूँ।'

नए एस ईवी को अपने उपयोक्ताओं के सहयोग के साथ विकसित किया गया है। इसे एक विशिष्ट रूप से तैयार पारितंत्र का समर्थन प्राप्त है, यह ई-कार्गो परिवहन के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है। एस ईवी समय पर लागत-प्रभावी और कुशल लास्ट-माइल डिलीवरीज़ करने की मुख्य जरूरत को संबोधित करने के अलावा, अपने सजग ग्राहकों की भावी प्रतिबद्धताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करेगा ताकि हम नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट हासिल कर सकें।

टाटा मोटर्स ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों एवं लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि अमेज़न, बिगबास्केट, सिटी लिंक, डीओटी, फ्लिपकार्ट, लेट्सट्रांसपोर्ट, मूविंग और येलो ईवी के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इसमें एस ईवी की 39,000 यूनिट्स प्रदान करना, अधिकतम फ्लीट अपटाइम के लिए समर्पित वाहन सहयोग केंद्र स्थापित करना, अगली पीढ़ी के इष्टतम फ्लीट प्रबंधन समाधान - टाटा फ्लीट एज को तैनात करना शामिल है। साथ ही हम टाट समूह की सम्बद्ध कंपनियों के प्रमाणित सक्षम पारितंत्र 'टाटा यूनिईवर्स' को भी सहयोग देंगे।

लॉन्च के मौके पर श्री गिरीश वाघ, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टाटा मोटर्स ने कहा, 'एस ईवी की पेशकश भारत में ज़ीरो-उत्सर्जन कार्गो परिवहन प्रदान करने के हमारे सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाती है। इलेक्ट्रिक बसों के हमारे अनुभव एवं सफलता के दम पर, हमने शहर में वितरण करने के लिए अलग-अलग इस्तेमाल के लिए विशिष्ट इलेक्ट्रिक वाहन समाधानों को डिजाइन किया है। ये समाधान तरह-तरह के प्रयोग करने की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं और सभी हितधारकों के लिए पूरी तरह पैसा वसूल होते हैं। हम अपने ई-कॉमर्स ग्राहकों से मिले सहयोग एवं प्रतिक्रिया से बहुत प्रोत्साहित हुए हैं, और हमने अब उनके साथ ज़ीरो-उत्सर्जन वाले कार्गो परिवहन का सफर आरंभ किया है।'

आयशर ट्रैक्टर्स ने लॉन्च किया प्राइमा G3

नए ज़माने के किसानों के लिए प्रीमियम ट्रैक्टर रेंज

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माता, टैफे - ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड समूह के आयशर ट्रैक्टर्स ने आयशर प्राइमा उ3 सीरीज़ लॉन्च करने की घोषणा की। प्रीमियम ट्रैक्टरों की एक पूरी नई रेंज - आयशर प्राइमा उ3 सीरीज़ नए ज़माने के भारतीय किसानों को ध्यान में रख कर निर्मित की गई है जो बेहतरीन स्टाइल वाले, कार्यक्षम और मज़बूत ट्रैक्टर की चाह रखते हैं। आयशर प्राइमा उ3 40-60 एच.पी. रेंज में ट्रैक्टरों की एक नई सीरीज़ है, जो दशकों के बेजोड़ अनुभव के साथ विकसित की गई शानदार स्टाइलिंग, उन्नत टेक्नोलॉजी और बेहतरीन आराम प्रदान करती है। आयशर प्राइमा उ3 सीरीज़ को लॉन्च करते हुए, टैफे की

सी.एम.डी. मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा 'दशकों से आयशर ब्रांड, कृषि और कॉमर्शियल - दोनों क्षेत्रों में अपने भरोसे, विश्वसनीयता, मजबूती और बहुमुखी उपयोगिता के लिए जाना जाता है। प्राइमा उ3 के लॉन्च से आधुनिक भारत के प्रगतिशील किसानों को अधिक उत्पादकता, आराम और आसान परिचालन का लाभ मिलेगा, जिसकी वे आकांक्षा करते हैं। साथ ही उन्हें कम लागत में ज़्यादा फ़ायदे का विकल्प भी प्राप्त होगा, जो सदा से आयशर का वादा रहा है।'

नया प्राइमा उ3 नए ज़माने के एरोडायनामिक बॉनेट के साथ आता है जो ट्रैक्टर को एक अनूठा, शानदार स्टाइल प्रदान करता है और यह वन-टच ओपन, सिंगल पीस बॉनेट इंजन तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिससे ट्रेक्टर का रख-रखाव आसान हो जाता है। उच्च तीव्रता वाली 3ॠ कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ बोल्ड ग्रिल, रैप-अराउंड हेडलाइट और डिजी-ॅॅऊ डैशबोर्ड इसे देखने में आकर्षक बनाते हैं और ज़्यादा क्रॉस-एयर फ्लो देते हैं जिससे इन ट्रैक्टरों का लंबे समय तक निरंतर परिचालन किया जा सकता है। टैफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड (टी.एम.टी.एल.) की डिप्टी एम.डी, डॉ. लक्ष्मी वेणु, ने कहा बताया कि, 'भारत के युवा और प्रगतिशील किसान टेक्नोलॉजी और कृषि-तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि कार्यों से अधिकतम लाभ हासिल करना चाहते हैं, और उनके लिए प्राइमा उ3 कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में आदर्श पार्टनर की भूमिका निभाएगा।'

डीएसपी फ्लेक्सी कैप ने पूरे किए 25 साल; 19.1% की सीएजीआर दर से दिया रिटर्न

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के 25 साल पूरे होने की घोषणा की है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड को 29 अप्रैल 1997 को लॉन्च किया गया था और यह समय के साथ साबित पोर्टफोलियो है जो कई बाजार चक्रों से गुजरते हुए अपनी स्थापनाङ के बाद से 19.% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर) दर से रिटर्न देने में सफल रहा है। शुरुआत में डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किए गए 1 लाख रुपये की पूंजी अब तक 78 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है, जबकि निफ्टी 500 टीआरआई में इसी तरह का निवेश बढ़कर 31.74 लाख रुपये ही हुआ। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड व्यापार की लंबी उम्र, विवेकपूर्ण प्रबंधन और विकास स्थिरता बीएमजी फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित करके निवेश के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाता है। फंड द्वारा अपनाए जाने वाले बीएमजी फ्रेमवर्क में ऐसे ०?यावसाय शामिल हैं जोकि पूंजी को लेकर कम गहन होते हैं, उनका उच्च नकद रूपांतरण होता है, साथ ही बाजार हिस्सेदारी पर प्रभुत्व, विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन, और उच्च आरओई और मुनाफे की वृद्धि दर को दर्शाते हुए बेहतर मार्जिन होता है। किसी भी 10 साल की अवधि में डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का सीएजीआर रोलिंग रिटर्न न्यूनतम 6.9% और अधिकतम 33.5% रहा है। जबकि, इक्विटी की तरह इस फंड में भी रुक-रुक कर एनएवी में उतार-चढ़ाव होता है लेकिन एक दशक से अधिक समय से इसने धैर्यवान निवेशकों के लिए सकारात्मक रिटर्न दिया है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का प्रबंधन अतुल भोले और अभिषेक घोष द्वारा किया जाता है।

खाद्य तेलों के आयात के लिए नए विकल्प तलाश रहा है भारतः सीतारमण

चेन्नई। एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि रूस एवं यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत खाद्य तेलों के आयात के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। सीतारमण ने यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के एक कार्यक्रम में कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से भारत को खाद्य तेलों के आयात में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ''खाद्य तेल के आयात में कई बाधाएं हैं। हम खाद्य तेलों का आयात नहीं कर पा रहे हैं। हमें सूरजमुखी तेल मिल रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है।'' भारत यूक्रेन से बड़े पैमाने पर सूरजमुखी तेल का आयात करता रहा है लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सीतारमण ने कहा, ''ऐसी स्थिति में हम कई दूसरे बाजारों से खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं और कुछ नए बाजारों पर भी हमारी नजर है।'' इसके साथ ही उन्होंने घरेलू कारोबारियों से इस मौके का फायदा उठाते हुए तेल निर्यात की संभावनाओं पर गौर करने को कहा। उन्होंने कहा, ''उद्योगपतियों को हरेक चुनौती को अवसर में बदलने का मौका देखना चाहिए। केंद्र सरकार अपना समर्थन देने के लिए हमेशा ही तैयार है।'' सीतारमण ने भारतीय उद्योगों से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में साझा उद्यम लगाने के लिए भागीदार तलाशने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ''इन दोनों देशों में साझा उद्यम साझेदार का चयन करने से घरेलू उद्यमियों के लिए अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी।'' भारत ने पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अधिकांश भारतीय उत्पादों को इन दोनों देशों में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।

बोइंग और एआईईएसएल ने प्रमुख भारतीय रक्षा प्लेटफॉर्म्स की मरम्मत और जांच के लिए सहयोग की घोषणा

भारतीय वायु सेना और नौसेना द्वारा संचालित विमानों के बेड़े की रख रखाव, मरम्मत और जांच करेंगे

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बोइंग ने भारत में बोइंग के प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों पर अहम उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत और निगरानी जांच (एमआरओ) के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के साथ सहयोग की घोषणा की है। भारत में बोइंग के महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म में भारतीय नौसेना द्वारा संचालित P-8I और भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित 777 वीआईपी विमान शामिल हैं। भारतीय नौसेना, एआईईएसएल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता-भागीदारों की मौजूदगी में 10 मई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा सम्मेलन में बोइंग इंडिया आत्मनिर्भरता में इस सहयोग की घोषणा की गई। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र आहूजा ने कहा,'एआईईएसएल के साथ हमारा नियोजित सहयोग हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी, असाधारण परिचानल क्षमता और अभियानों की तत्परता को सक्षम बनाते हुए स्थानीय रूप से हमारे रक्षा ग्राहकों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने की स्थिति में ला सकता है। साथ ही यह भारत को क्षेत्रीय एमआरओ हब बनाने की भारत सरकार के आत्मानिर्भर भारत की नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।''

भारतीन नौसेना के लिए त्वरित बदलाव को सुनिश्चित करते हुए यह साझेदारी भारतीय नौसेना के बढ़ते पी-8आई बेड़े को सहयोग प्रदान करेगी और साथ ही स्थानीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में भी मदद करेगी। यह देसी एमआरओ क्षमता के निर्माण में भी मदद करेगा क्योंकि इसके तहत भारत में पहली बार पी-8आई के लैंडिंग गियर की मरम्मत और निगरानी जांच की शुरुआत होगी। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ शरद अग्रवाल ने कहा, 'इस तरह का सहयोग भारत में एमआरओ क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। हम इसे लेकर बेहद उत्साहित और प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हम बोइंग इंडिया रिपेयर डिवेलपमेंट एंड सस्टेनमेंट (BIRDS) हब पहल के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को बेहद अहम सहयोग प्रदान कर रहे हैं।''

एआईईएसएल के साथ बोइंग इंडिया का सहयोग BIRDS हब पहल को और गति प्रदान करेगा। बर्ड्स हब पहल भारत के भीतर देसी नेटवर्क और बोइंग के नेतृत्व वाली आपूर्तिकर्ताओं का गठबंधन है, जिसके तहत रक्षा और वाणिज्यिक विमानों के इंजीनियरिंग, रख रखाव, कौशल विकास, मरम्मत और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी एमआरओ पारितंत्र के निर्माण की कल्पना की गई है। यह हब भारी रख रखाव, कल पुर्जों की मरम्मत, प्रशिक्षण और एमआरओ का काम करने वाले लोगों के कौशल विकास के मामले में व्यापक क्षमताओं को समेटे हुए हैं, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। BIRDS का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत में उच्च गुणवत्ता वाली एमआरओ क्षमताओं का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना है, ताकि मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति करने वाले उप-आपूर्तिकर्ताओं और मध्यम, लघ व सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) को विकसित कर प्रशिक्षित या कौशल संपन्न मानव संसाधन को बढ़ाया जा सके।

अप्रैल में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या 83 प्रतिशत बढ़ी : इक्रा

मुंबई। एजेंसी

कोविड महामारी का प्रकोप कम होने से अप्रैल में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या सालाना आधार पर 83 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.05 करोड़ रहने का अनुमान है। यह महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में मात्र पांच प्रतिशत कम है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को यह जानकारी दी। अप्रैल, 2019 में भारतीय एयरलाइंस से 1.1 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी। इक्रा ने कहा कि घरेलू एयरलाइनों के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या महामारी-पूर्व के स्तर करीब 1.83 करोड़ को पार कर 1.85 करोड़ पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा हुए भू-राजनीतिक मुद्दों की वजह से विमान ईंधन (एटीएफ) के बढ़ते दाम पुनरुद्धार की प्रक्रिया के लिए एक बड़ा खतरा हैं। इक्रा के उपाध्यक्ष और खंड प्रमुख सुप्रियो बनर्जी ने बताया कि अप्रैल, 2022 में औसतन रोजाना 2,726 उड़ानें रवाना हुईं, जो पिछले वर्ष के समान महीने के 2,000 के आंकड़े से अधिक है। यह मार्च, 2022 के आंकड़े 2,588 से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में घरेलू एयरलाइन परिचालन में लगभग सामान्य हालात को देखते हुए यात्री यातायात में पुनरुद्धार तुलनात्मक रूप से तेज गति से होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एटीएफ की ऊंची कीमतों उद्योग के लिए चुनौती बनी हुई है और यह भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे को प्रभावित करेंगी।

राज्यों के कानून के तहत नहीं हो सकता एनबीएफसी का नियमनः न्यायालय

नयी दिल्ली। एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के तहत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का नियमन राज्य सरकारों के कानून के जरिये नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि एनबीएफसी देश की वित्तीय सेहत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका नियंत्रण रिजर्व बैंक के पास रहता है। पीठ ने कहा, ''ऐसे में यह कहना कि इतने महत्वपूर्ण मामले में रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, केंद्रीय बैंक के पास मौजूद सांविधिक नियंत्रण को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा।'' पीठ ने कहा, ''यह शायद सही है कि कई बार एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले कर्ज के ब्याज पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्रीय बैंक के पास इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है।'' रिजर्व बैंक इस सवाल की समीक्षा कर रहा था कि क्या रिजर्व बैंक के नियमन के तहत आने वाले एनबीएफसी का केरल के साहूकर अधिनियम, 1958 और गुजरात साहूकार कानून, 2011 के तहत भी नियमन किया जा सकता है? शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सोच-विचार के बाद यह राय बनती है कि केरल के कानून और गुजरात के कानून को रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत और केंद्रीय बैंक के नियमन वाले एनबीएफसी पर लागू नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, ''ऐसे में केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एनबीएफसी की सभी अपीलों को मंजूरी दी जाती है। इसी तरह गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार की अपीलों को खारिज किया जाता है।''

बच्चे संग ट्रेवल करने वाली महिलाओं का सफर होगा आसान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

हममें से अधिकतर लोगों के परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ होगा। आपने भी नवजात या छोटे बच्चे के साथ सफर करने वाली महिलाओं को ट्रेन में देखा होगा। वे अपने बच्चों को पूरा स्पेस उपलब्ध कराने के लिए काफी कष्ट करती हैं। लेकिन अब उन्हें सफर के दौरान कष्ट नहीं करना होगा। रेलवे ने प्रायोगिक आधार पर ऐसी बर्थ बनाई है, जिसमें आराम से बच्चे के संग यात्रा की जा सकती है।

क्या है बेबी बर्थ

रेल प्रशासन छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को 'बेबी बर्थ' देने की व्यवस्था की है। फिलहाल यह व्यवस्था नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली लखनऊ मेल में की गई है। लखनऊ मेल के एक डिब्बे में ऐसे दो बर्थ की व्यवस्था की गई है। रेलवे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसमें रेगुलर बर्थ में ही छोटा सा बर्थ जोड़ा गया है। इसके खोल लेने पर उस बर्थ की चौड़ाई बढ़ जाती है।

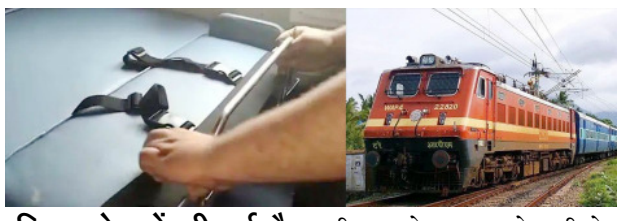

किस कोच में की गई है व्यवस्था

मदर्स डे पर यह व्यवस्था हुई है। लखनऊ-नई दिल्ली के बीच चलने वाली लखनऊ मेल(12229-30) के एसी-कोच में इस विशेष बर्थ की व्यवस्था की गई है। रेलवे के अनुसार रविवार की रात को लखनऊ से चली ट्रेन के बी-4 कोच (संख्या-194129) की बर्थ 12 व 60 को अलग से बेबी सीट जोड़ी गई है। एक्सट्रा सीट से महिलाएं अपने नवजात के संग आराम से ट्रेन में सफर कर सकेगी। खास यह कि बेबी सीट को जरुरत पर फोल्ड भी किया जा सकता है।

कोई अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा

अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बेबी बर्थ के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। तो बता दें, कि रेलवे बच्चे की बर्थ के लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं लेगा। इसके लिए रिजर्व टिकट खरीदते समय ही बताना होगा। उस समय रिजर्वेशन फार्म में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के नाम का खुलासा करना होगा और बेबी बर्थ मिल जाएगा।

लोगों को पसंद आया तो अन्य ट्रेन में भी

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्रायोगिक आधार पर बेबी बर्थ की व्यवस्था की गई है। यदि यह व्यवस्था लोगों को पसंद आएगी तो इसका विस्तार अन्य ट्रेनों में भी किया जा सकता है। इस पर यात्रियों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। साथ ही देखा जाएगा कि इस बर्थ से ट्रेन के दूसरे यात्रियों को भी परेशानी नहीं हो। कब तक हो पाएगा ऐसा, इस सवाल पर उनका कहना है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।